IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजस्थान के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका

डॉ.ओम प्रकाश मीना

सहायक आचार्य – ईएएफएम

स्व.पं.न.कि.श.राजकीय महाविद्यालय,दौसा

ग्रामीण विकास किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का मूल आधार होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ आज भी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण विकास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँकृजैसे मरुस्थल, जल की कमी, अनियमित वर्षा और संसाधनों की सीमित उपलब्धताकृग्रामीण जीवन को प्रभावित करती हैं, वहाँ योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता अत्यधिक होती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में National Bank for Agriculture and Rural Development (नाबार्ड) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।

नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना, ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करना तथा गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है। नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के विलय से बना है। यह संस्था वित्तीय सहायता के साथ–साथ विकासात्मक और पर्यवेक्षी भूमिका भी निभाती है।

राजस्थान में नाबार्ड की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित है। राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की अनिश्चितता और जल संकट के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। नाबार्ड ने इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए हैं। राजस्थान के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका बहुआयामी रही है। सबसे पहले, नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य में जल की कमी को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया है। इससे न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों

की आय में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी नाबार्ड किसानों को प्रोत्साहित करता है।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। नाबार्ड द्वारा संचालित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से सड़कों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है और बाजारों तक पहुँच आसान हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी नाबार्ड की भूमिका सराहनीय है। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें बचत और ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर रही हैं। राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में के माध्यम से महिलाओं ने लघु उद्योग स्थापित किए हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन और किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करानाकृये सभी कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक रहे हैं।

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. कृषि और पशुपालन पर निर्भरता
2. वर्षा आधारित खेती
3. मरुस्थलीय एवं अर्ध–शुष्क क्षेत्र
4. सीमित सिंचाई सुविधाएँ
5. ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी

इन विशेषताओं के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करना आवश्यक होता है, जिसमें नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजस्थान के ग्रामीण विकास का आधार कृषि है। नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई पहलें की हैं –

1. **जलागम विकास** : राजस्थान में जल की कमी एक प्रमुख समस्या है। नाबार्ड ने जलागम विकास परियोजनाओं के माध्यम से वर्षा जल संचयन, मिट्टी संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार के प्रयास किए हैं। इन परियोजनाओं से भूमि की उत्पादकता बढ़ी है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

2. **सूक्ष्म सिंचाई और जल प्रबंधन** : नाबार्ड ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया है, जिससे जल का कुशल उपयोग संभव हुआ है। यह तकनीक विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है।
3. **जैविक खेती और नवाचार** : नाबार्ड जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करता है। इससे कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हुआ है।

नाबार्ड द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे किसान संगठित होकर अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच पा रहे हैं।हालांकि, नाबार्ड के प्रयासों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, तकनीकी ज्ञान का अभाव और ऋण वितरण में देरी जैसी समस्याएँ विकास की गति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जाए।

नाबार्ड ने राजस्थान के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से कृषि, अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यदि भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो नाबार्ड ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है तथा राजस्थान को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है। NABARD ने राजस्थान के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। भविष्य में यदि योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाए, तो ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकती है।

सारांश में कह सकते हैं कि नाबार्ड ने राजस्थान के ग्रामीण विकास में एक सशक्त और प्रभावी भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से कृषि, अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो नाबार्ड भविष्य में ग्रामीण विकास को और अधिक गति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, नाबार्ड न केवल एक वित्तीय संस्था है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के समग्र विकास का आधार स्तंभ है, जो राजस्थान जैसे राज्य में सतत और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

संदर्भ :

1. बंसत देसाई : ग्रामीण विकास की मूल अवधारणाएं
2. ए.एन. अग्रवाल : ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गहरी समझ
3. पी.एल. अरोड़ा : रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया
4. मनोज मिश्रा : इकोनोमिक आफ रूरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया
5. पंजाब केसरी पत्रिका।